नई दिल्ली | 18 सितंबर 2017 सोमवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिजली की राह चला सार्वजनिक परिवहन

ज्योति मुकुल
नई दिल्ली, 17 सितंबर

वाहन विनिर्माताओं पर सरकार ने तो दबाव अब डाला कि वे 2030 तक बिजली से चलने वाले वाहनों का रुख करें, लेकिन सार्वजनिक परिवहन बहुत पहले से ही यात्रा के लिए स्वच्छ ईंधन की राह पकड़ चुका है। छह से ज्यादा शहरों और राज्यों में या तो पहले से ही ई-बसें चल रही हैं, या वे इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।

उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के ई-वाहन की ओर बढ़ने की एक वजह यह है कि इससे उनके लिए बेहतर वातावरण तैयार करना आसान है। ईवी मोटर्स इंडिया के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक विनीत बंसल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग बढ़ सकता है क्योंकि उनका नियत मार्ग होता है और उनकी चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करना आसान होगा। सार्वजनिक परिवहन से किसी भी शहर के लोगों की यातायात जरूरतों की 85 प्रतिशत मांग पूरी करने की क्षमता है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक बसों के कल पुर्जे भारत में स्थानीय रूप से बनने लगेंगे और ई बसें बनाने की लागत में खासी कमी आएगी। लागत घटने पर निजी ऑपरेटरों के लिए परिचालन व्यावहारिक हो जाएगी।'

बहरहाल फ्रांस की श्नाइडर इलेक्ट्रिक के भारत के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन दोनों को साथ साथ ई-वाहन की ओर बढ़ना चाहिए।

कर्नाटक सरकार हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाई है, जो सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाला पहला राज्य है। बेंगलूरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 2014 में चीन की बीवाईडी इलेक्ट्रिक बसें चलानी शुरू की थी और यह बेंगलूरु की सड़कों पर 3 महीने प्रायोगिक तौर पर चलीं। दिसंबर 2015 में टेक्नोलॉजी प्रदाता केपीआईटी और केंद्रीय सड़क तकनीक संस्थान (सीआईआरटी) ने इलेक्ट्रिक बस की स्वदेशी तकनीक पेश की। तमाम शहरों में नई ई-बस चालू करने के पहले रेट्रोफिटिंग से शुरुआत की गई। उदाहरण के लिए सीआईआरटी और केपीआईटी ने पुणे में 2016 में 12 पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बस में रेट्रोफिटिंग के लिए निविदा निकाली। अब पुणे नगर निगम 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने पर विचार कर रहा है और उसने पहले ही इसके लिए रुचि पत्र जारी कर दिया है।

जुलाई 2016 में हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बैटरी से चलने वाले 25 यात्री परिवहन वाहनों की डिजाइन, विनिर्माण और आपूर्ति के लिए निविदा जारी की। इसी साल अप्रैल में मुंबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बेस्ट ने अपनी 5 पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने के लिए निविदा जारी की। इस साल की शुरुआत में जनवरी में बेस्ट ने एक और निविदा 6 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए निकाली।

उद्योग जगत के अनुमान के मुताबिक भारत में निजी क्षेत्र की 15 लाख और सार्वजनिक क्षेत्र की 1.5 लाख बसें चल रही हैं और भारत में कुल 16.5 लाख बसें हैं। बंसल ने कहा, 'उम्मीद है कि अगले 10 साल में यह सभी बसें बिजली से चलने वाली बसों में तब्दील हो जाएंगी।'

2012-13 में 25 करोड़ से ज्यादा यात्री रोजाना सरकारी बसों में यात्रा करते थे। भारत की आबादी 2021 तक 1.35 अरब हो जाने की संभावना है, जिनमें से 55 करोड़ शहरी क्षेत्र में होंगे। बंसल ने कहा कि तब तक 6,44,800 बसों की जरूरत होने का अनुमान है।

विभिन्न राज्यों की स्थिति

- हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बैटरी चालित 25 यात्री वाहन चल रहे हैं
- बेस्ट, मुंबई ने ई-बसें खरीदने की योजना बनाई है और 5 पुरानी बसों को ई-बस में तब्दील किया है
- सीआईआरटी और केपीआईटी ने पुणे में 12 पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बस में बदला है
- बेंगलूरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहता है
- इंदौर और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट भी इच्छुक